

रायपुर जिले में 6-14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण की प्रभावशीलता का तुलनात्मक समाजशास्त्रीय अध्ययन

भूमिका शर्मा

शोधार्थी

समाजशास्त्र विभाग, कला संकाय

आंजनेय विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492101

संपर्क ईमेल: bhumisharma25@gmail.com

डॉ. प्रीति उपाध्याय

विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग

कला संकाय, आंजनेय विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492101

शोध सारांश (Abstract)

यह शोध रायपुर जिले के 6-14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण की प्रभावशीलता का तुलनात्मक समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि क्या ऑनलाइन शिक्षण विद्यालय आधारित प्रत्यक्ष शिक्षण का प्रभावी विकल्प बन सकता है, विशेषकर समाजीकरण, शैक्षणिक उपलब्धि और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में। अध्ययन तुलनात्मक एवं वर्णनात्मक शोध प्रारूप पर आधारित है। 387 उत्तरदाताओं—विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, कोचिंग प्रतिनिधियों तथा समुदाय सदस्यों—से स्तरित यादृच्छिक न्यादर्श द्वारा तथ्य संकलित किए गए। विश्लेषण हेतु प्रतिशत, मध्यमान, काई-वर्ग परीक्षण, टी-परीक्षण तथा सहसंबंध का उपयोग किया गया। निष्कर्षतः ऑनलाइन शिक्षण सहायक साधन के रूप में उपयोगी है, किंतु प्रत्यक्ष शिक्षण का पूर्ण विकल्प नहीं; अतः डिजिटल समावेशन, परामर्श और ग्रामीण अवसंरचना के साथ संतुलित हाइब्रिड मॉडल अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

मुख्य शब्द: ऑनलाइन शिक्षा; ऑफलाइन शिक्षण; डिजिटल विभाजन; समाजीकरण; शिक्षा का समाजशास्त्र; रायपुर जिला

1. प्रस्तावना (Introduction)

“शिक्षा केवल जीवन की तैयारी नहीं है; शिक्षा स्वयं जीवन है।” — जॉन डेवी (John Dewey)

शिक्षा समाज की वह आधारशिला है जिसके माध्यम से समाज अपना पुनरुत्पादन करता है। यह केवल ज्ञान प्रदान नहीं करती, बल्कि समाजीकरण (Socialization) की उस प्रक्रिया को पूर्ण करती है जिसके द्वारा बालक भाषा, अनुशासन, सहानुभूति और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना अर्जित करता है। एमिल दुर्खीम (Durkheim, 1956) ने विद्यालय को उस संस्था के रूप में देखा जिसके माध्यम से समाज अपनी नैतिक व्यवस्था नई पीढ़ी पर अंकित करता है, तथा जॉन डेवी (Dewey, 1916) के अनुसार शिक्षा और सामाजिक जीवन एक-दूसरे से अविभाज्य हैं। इस दृष्टि से विद्यालय पाठ्यक्रम का वितरण माध्यम नहीं, बल्कि एक लघु समाज (Miniature Society) है।

इक्कीसवीं सदी ने इस समझ को चुनौती दी है। सूचना अब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किंतु वे परिवेश संकुचित हो गए हैं जिनमें बच्चे सहजीवन सीखते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यालयों के बंद होने ने शिक्षण की एक प्रयोगात्मक पद्धति को एकमात्र उपलब्ध पद्धति में परिवर्तित कर दिया और डिजिटल कक्षा करोड़ों भारतीय बच्चों का सामान्य अनुभव बन गई। तत्पश्चात् राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मिश्रित शिक्षण (Blended Learning) को औपचारिक नीतिगत स्थान प्रदान किया (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। अतः एक मौलिक प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होता है: **क्या स्क्रीन की चमक, एक शिक्षक की आँखों की चमक और कक्षा की जीवंत चर्चाओं का वास्तविक स्थान ले सकती है?**

1.1 शोध की पृष्ठभूमि (Research Background)

परंपरागत रूप से भारत में ऑफलाइन अथवा प्रत्यक्ष शिक्षण ही समाजीकरण का मुख्य माध्यम रहा है। विद्यालय वह स्थल है जहाँ बालक पहली बार परिवार के बाहर सत्ता, मित्रता, प्रतिस्पर्धा और सहयोग से परिचित होता है। इसके विपरीत, ऑनलाइन शिक्षण व्यक्तिगत (Individualise) कर देता है। यह सहपाठी समूह, खेल के मैदान और उस अनियोजित अंतःक्रिया को हटा देता है जिसे समाजशास्त्री दीर्घकाल से अनौपचारिक पाठ्यक्रम के रूप में चिह्नित करते आए हैं। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक एवं शैक्षणिक केंद्र रायपुर जिला इस परिवर्तन के अध्ययन हेतु विशेष रूप से उपयुक्त क्षेत्र है। इस जिले में एक ओर सघन सुविधाओं से युक्त शहरी केंद्र है, तो दूसरी ओर आरंग एवं धरसीवा ब्लॉकों का ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी परिवेश। अतः एक ही प्रशासनिक इकाई के भीतर नीति और भाषा को स्थिर रखते हुए डिजिटल सुलभता की अत्यंत भिन्न परिस्थितियों की तुलना संभव है।

1.2 वैश्विक एवं राष्ट्रीय परिदृश्य

यूनेस्को (UNESCO, 2024) की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल तकनीक ने शिक्षा की पहुँच तो बढ़ाई है, किंतु यह शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के मानवीय स्पर्श (Human Touch) का स्थान लेने में असमर्थ रही है; रिपोर्ट चेतावनी देती है कि दीर्घकालिक स्क्रीन-टाइम बच्चों के सामाजिक व्यवहार को सीमित करता है। विश्व बैंक ने अधिगम निर्धनता (Learning Poverty) के आँकड़ों के माध्यम से इस शैक्षणिक क्षति के परिमाण को रेखांकित किया है, जिसके अनुसार निम्न एवं मध्यम-आय वाले देशों में अधिकांश बच्चे दस वर्ष की आयु तक साधारण अनुच्छेद पढ़ने में असमर्थ थे, और महामारीकालीन विद्यालय-बंदी के पश्चात यह अनुपात और बढ़ा।

भारतीय संदर्भ में असर रिपोर्ट (ASER Centre, 2023) ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी भाषाई एवं गणितीय दक्षता में गिरावट दर्ज करती है, जो डिजिटल निर्भरता की अवधि से संबद्ध है। यह निष्कर्ष रायपुर जैसे जिलों के ग्रामीण अंचलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ उपकरणों की साझेदारी, अनियमित विद्युत आपूर्ति और सीमित बैंडविड्थ ने ऑनलाइन कक्षा के वास्तविक अनुभव को निर्धारित किया।

1.3 समाजशास्त्रीय द्वंद्व: ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन

पियरे बोरदियू के सांस्कृतिक पूँजी (Cultural Capital) के सिद्धांत के अनुसार किसी भी शैक्षणिक व्यवस्था का लाभ असमान रूप से उन बच्चों को प्राप्त होता है जिनके परिवारों के पास पूर्व से ही आवश्यक सामाजिक एवं भौतिक संसाधन विद्यमान हैं। ऑनलाइन शिक्षण पर इस तर्क को लागू करने पर यह अनुमान निकलता है कि स्क्रीन-आधारित अधिगम की ओर संक्रमण विद्यमान असमानता को घटाने के स्थान पर बढ़ाएगा, क्योंकि उपकरण, डेटा संयोजन और अभिभावकीय पर्यवेक्षण की क्षमता स्वयं असमान रूप से वितरित हैं। मैनुअल कास्टेल्स की नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा सूचना अधिसंरचना तक पहुँच को शक्ति का रूप मानकर इस व्याख्या को पुष्ट करती है, जबकि नील पोस्टमैन की तकनीकी-प्रभुत्व (Technopoly) की समीक्षा चेतावनी देती है कि तकनीक तटस्थ साधन बनी नहीं रहती, वरन संस्कृति और मानवीय अंतःक्रिया को अपने ही तर्क के अनुसार पुनर्गठित करने लगती है।

1.4 रायपुर जिले का विशेष संदर्भ

रायपुर जिले के भीतर एक स्पष्ट डिजिटल विभाजन (Digital Divide) उभरकर सामने आता है। रायपुर नगर निगम के शहरी वार्डों में व्यावहारिक रूप से सार्वजनिक इंटरनेट उपलब्धता तथा निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों के सघन तंत्र ने ऑनलाइन शिक्षण को एक कार्यसाध्य विकल्प बनाया। इसके विपरीत आरंग एवं धरसीवा के ग्रामीण भागों में स्थिर कनेक्टिविटी का अभाव तथा साझा या अनुपलब्ध उपकरणों के कारण ऑनलाइन शिक्षण अनेक बार केवल औपचारिक रह गया। अतः एक ही नीति ने एक ही जिले के भीतर पर्याप्त रूप से भिन्न शैक्षणिक यथार्थ उत्पन्न किए।

1.5 समस्या का कथन (Statement of the Problem)

प्रस्तुत अध्ययन की समस्या रायपुर जिले के 6-14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण की तुलनात्मक प्रभावशीलता है, जिसकी पड़ताल शैक्षणिक के स्थान पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से की गई है। यह आयु वर्ग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही प्राथमिक समाजीकरण की अवधि है जिसमें विद्यालय अंतःक्रिया, अनुशासन और सामूहिक उत्तरदायित्व को आकार देने वाली प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जहाँ ऑनलाइन शिक्षण प्रत्यक्ष संवाद को विस्थापित करता है, वहाँ इसके परिणाम मापे गए शैक्षणिक निष्पादन से आगे बढ़कर बालक के सामाजिक निर्माण तक विस्तृत हो जाते हैं। अतः यह अध्ययन केवल यह नहीं पूछता कि कौन-सी पद्धति अधिक प्रभावी रूप से पढ़ाती है, बल्कि यह भी कि कौन-सी पद्धति समाजीकरण को बनाए रखती है, और किनके लिए।

1.6 अध्ययन की आवश्यकता (Need of the Study)

- डिजिटल विभाजन को समझना:** रायपुर जिले में शहरी आधुनिकता और ग्रामीण सादगी का अनूठा मेल है। रायपुर शहर तथा आरंग एवं धरसीवा के ग्रामीण अंचलों के बीच संसाधनों के अंतर का मापन डिजिटल शिक्षा नीति के किसी भी यथार्थपरक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है।
- समाजीकरण के बदलते स्वरूप का अध्ययन:** 6-14 वर्ष की आयु प्राथमिक समाजीकरण की अवधि है और परंपरागत रूप से विद्यालय इसकी मुख्य एजेंसी रहे हैं। ऑनलाइन माध्यमों ने इस भूमिका को किस सीमा तक परिवर्तित किया है, इसकी अनुभवजन्य पड़ताल आवश्यक है।
- शैक्षणिक गुणवत्ता का मूल्यांकन:** असर एवं यूनेस्को जैसी संस्थाओं ने बुनियादी कौशलों में गिरावट की चेतावनी दी है। यह प्रवृत्ति रायपुर जिले में किस सीमा तक लागू होती है, इसके लिए स्थानीय साक्ष्य अपेक्षित हैं।
- मानसिक एवं सामाजिक प्रभाव का आकलन:** बढ़ता स्क्रीन-टाइम, बढ़ता एकाकीपन (Isolation) और शारीरिक गतिविधियों में कमी एक गंभीर समाजशास्त्रीय चिंता है, जिसकी गहराई इस क्षेत्र में मापी नहीं गई है।

1.7 शोध का महत्व (Significance of the Study)

- शैक्षणिक महत्व:** यह अध्ययन समाजीकरण के पारंपरिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को डिजिटल परिवेश के संदर्भ में नए साक्ष्य प्रदान करता है।
- सामाजिक उपयोगिता:** यह शहरी एवं ग्रामीण रायपुर के बीच की डिजिटल खाई का प्रलेखन करता है और उस सामाजिक दूरी को दृश्यमान बनाता है जो तकनीक सुविधा के साथ-साथ उत्पन्न कर सकती है।
- नीतिगत प्रासंगिकता:** निष्कर्ष छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग एवं नीति-निर्माताओं को ग्रामीण क्षेत्रों हेतु अधिक संतुलित एवं समावेशी व्यवस्था के निर्माण में सहायक होंगे।

- **अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन:** अध्ययन ऑनलाइन शिक्षण के दौरान बच्चों के मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा तथा हाइब्रिड पद्धतियों के उत्तरदायी उपयोग का आधार प्रस्तुत करता है।
- **भविष्य के शोध का आधार:** एक जिले के तुलनात्मक विवरण के रूप में यह अध्ययन परवर्ती शोध हेतु आधार दस्तावेज के रूप में कार्य कर सकता है।

2. संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन (Literature Review)

इस अनुभाग में उन प्रमुख रिपोर्टों, अध्ययनों एवं सैद्धांतिक कृतियों का सारांश प्रस्तुत है जो ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण के समाजशास्त्रीय विश्लेषण का आधार बनाती हैं।

2.1 वैश्विक परिदृश्य

यूनेस्को (2024) ने *Technology in Education: A Tool on Whose Terms* में निष्कर्ष निकाला है कि डिजिटल तकनीक ने शिक्षा का विस्तार किया है, किंतु वह शिक्षक और अधिगमकर्ता के मानवीय संबंध का स्थान नहीं ले सकती, तथा अत्यधिक स्क्रीन-टाइम बच्चों के सामाजिक व्यवहार को संकुचित करता है। **विश्व बैंक** का अधिगम निर्धनता संबंधी कार्य दस वर्षीय बच्चों की बुनियादी पठन क्षमता में पर्याप्त कमी का प्रलेखन करता है, जो उन क्षेत्रों में और गंभीर हुई जहाँ तकनीकी संसाधन सीमित थे और शिक्षण पर्याप्त सहायता के बिना ऑनलाइन स्थानांतरित हुआ। **लिविंगस्टोन एवं सेफ्टन-ग्रीन (Livingstone & Sefton-Green, 2016)** इसका नृजातीय समकक्ष प्रस्तुत करते हैं और दर्शाते हैं कि डिजिटल माध्यम विद्यालयी आयु के बच्चों के दैनिक सामाजिक संसार को कैसे पुनर्गठित करते हैं।

2.2 राष्ट्रीय परिदृश्य (भारत)

असर केंद्र (2023) ग्रामीण भारत में बुनियादी अंकगणितीय एवं भाषाई दक्षता में गिरावट की सूचना देता है, जो डिजिटल निर्भरता की अवधि से संबद्ध है और रायपुर जिले के ग्रामीण ब्लॉकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (शिक्षा मंत्रालय, 2020)** मिश्रित शिक्षण की संस्तुति करती है और साथ ही डिजिटल विभाजन को पाटने की चुनौती को भी स्वीकार करती है। भारतीय शिक्षा-समाजशास्त्र की पूर्ववर्ती परंपरा—जयराम (2015), शाह एवं शाह (2006) तथा चौहान (2010)—वह ढाँचा प्रस्तुत करती है जिसमें विद्यालयी शिक्षा को गतिशीलता एवं स्तरीकरण दोनों का साधन माना जाता है, जबकि रामचंद्रन (2004) प्राथमिक शिक्षा में सुलभता की श्रेणीबद्धता का प्रलेखन करती हैं।

2.3 सैद्धांतिक ढाँचा (Theoretical Framework)

पियरे बोरदियू (1979, 1986) ने *Distinction* तथा पूँजी के स्वरूपों संबंधी अपने विवेचन में तर्क दिया कि शैक्षणिक सफलता पर्याप्त सीमा तक परिवार के भीतर उपलब्ध सांस्कृतिक एवं भौतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में जिन परिवारों के पास श्रेष्ठ उपकरण एवं कनेक्टिविटी है, वे उस लाभ को शैक्षणिक उपलब्धि में परिवर्तित कर लेते हैं।

मैनुअल कास्टेल्ल्स (1996) ने *The Rise of the Network Society* में यह मत प्रस्तुत किया कि समकालीन समाज में सूचना तक पहुँच ही शक्ति का आधार है। यह प्रस्थापना डिजिटल विभाजन को अस्थायी असुविधा के स्थान पर असमानता की संरचना के रूप में देखने की वैचारिक शब्दावली प्रदान करती है।

नील पोस्टमैन (1992) ने *Technopoly* में तर्क दिया कि तकनीक कभी केवल उपकरण नहीं रहती; वह संस्कृति एवं मानवीय संचार को शासित करने लगती है। यह तर्क इस अपेक्षा को पुष्ट करता है कि ऑनलाइन शिक्षण बच्चों के स्वाभाविक समाजीकरण का केवल माध्यम नहीं बनता, बल्कि उसे पुनर्संचित करता है।

बेसिल बर्नस्टीन (1971) ने *Class, Codes and Control* में **कोड थ्योरी** के माध्यम से सिद्ध किया कि सामाजिक पृष्ठभूमि बच्चों के सीखने और संवाद करने के तरीकेतरीकों को निर्धारित करती है। उनका ढाँचा रायपुर के ग्रामीण एवं शहरी बच्चों के बीच देखे गए अंतरों की व्याख्या में सहायक है। स्तरित सुलभता संबंधी पूरक कार्यों में **सेल्विन (2004)**, **हरगिटाई (2002)** का द्वितीय-स्तरीय डिजिटल विभाजन तथा **वैन डाइक (2005)** उल्लेखनीय हैं।

2.4 शोध अंतराल (Research Gap)

साहित्य से स्पष्ट है कि ऑनलाइन शिक्षा के प्रभावों की पड़ताल वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार से हुई है। किंतु छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा ग्रामीण-शहरी विभाजन के परिप्रेक्ष्य में 6–14 वर्ष के बच्चों के समाजीकरण पर कोई ठोस तुलनात्मक अध्ययन उपलब्ध नहीं है। अधिकांश उपलब्ध शोध तकनीकी एवं शिक्षणशास्त्रीय आयामों पर केंद्रित हैं। प्रस्तुत अध्ययन असमान डिजिटल सुलभता से उत्पन्न बच्चों के व्यवहार एवं सामाजिक मूल्यों के परिवर्तनों की पड़ताल कर इस अंतराल को भरने का प्रयास करता है।

3. शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. 6–14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के बीच ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण पद्धतियों की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. 6–14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के सीखने के स्तर एवं उनके व्यवहार पर ऑनलाइन शिक्षण के पढ़ने वाले प्रभाव की जाँच करना।
3. विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति तथा उससे उत्पन्न होने वाले डिजिटल विभाजन के बीच संबंधों का विश्लेषण करना।

4. रायपुर जिले के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों (शहरी एवं ग्रामीण) के आधार पर विद्यार्थियों के बीच डिजिटल अंतराल एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

4. शोध समस्या एवं परिकल्पनाएँ (Research Problem and Hypotheses)

4.1 शोध समस्या

शोध समस्या इस प्रकार निरूपित है: डिजिटल संसाधनों के क्षेत्र एवं आय वर्ग के अनुसार असमान वितरण को देखते हुए, रायपुर जिले के 6-14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा एवं समाजीकरण के माध्यम के रूप में ऑनलाइन शिक्षण किस सीमा तक और किन सामाजिक परिणामों के साथ ऑफलाइन शिक्षण का स्थान ले सकता है?

4.2 शोध प्रश्न (Research Questions)

1. क्या रायपुर के 6-14 वर्ष के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में ऑफलाइन शिक्षण पद्धति, ऑनलाइन की तुलना में सार्थक रूप से अधिक सफल है?
2. ऑनलाइन शिक्षण पद्धति ने विद्यार्थियों के सामाजिक संवाद एवं प्राथमिक समाजीकरण को किस सीमा तक प्रभावित किया है?
3. विद्यार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि उनके बीच सार्थक डिजिटल विभाजन निर्मित करने में कितनी प्रभावी है?
4. रायपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के बीच तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता में क्या सार्थक अंतर है?
5. क्या 6-14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन की तुलना में ऑफलाइन शिक्षण की सार्थक प्राथमिकता अधिक है?

4.3 शोध परिकल्पनाएँ (Hypotheses)

परीक्षण हेतु निम्नलिखित वैकल्पिक परिकल्पनाएँ निर्मित की गईं। प्रत्येक का परीक्षण उसकी संबंधित शून्य परिकल्पना (अंतर अथवा संबंध के अभाव) के विरुद्ध किया जाएगा।

1. H1: डिजिटल संसाधनों की कमी के कारण रायपुर के शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों में ऑनलाइन शिक्षण की प्रभावशीलता एवं शैक्षणिक परिणाम सार्थक रूप से कम हैं।
2. H2: ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक संवाद के स्तर में सार्थक रूप से कमी आई है।
3. H3: आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के विद्यार्थियों की तुलना में निम्न-आय वर्ग के विद्यार्थियों के मध्य एक सार्थक डिजिटल विभाजन विद्यमान है।
4. H4: शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मध्य एक सार्थक डिजिटल विभाजन विद्यमान है।
5. H5: 6-14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन की तुलना में ऑफलाइन शिक्षण की सार्थक प्राथमिकता अधिक है।

5. शोध कार्यविधि (Research Methodology)

5.1 शोध का प्रारूप (Research Design)

प्रस्तुत शोध तुलनात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। इसमें रायपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की तुलना की गई है।

सारणी 1. शोध के आयाम

आयाम	विवरण
शोध का प्रारूप	तुलनात्मक एवं वर्णनात्मक अध्ययन
अध्ययन क्षेत्र	छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला (रायपुर नगर निगम क्षेत्र; आरंग एवं धरसीवा ब्लॉक)
उत्तरदाता	6-14 वर्ष के स्कूली बच्चे, अभिभावक, शिक्षक, कोचिंग प्रतिनिधि एवं समुदाय के सदस्य
न्यादर्श आकार	कुल 387 उत्तरदाता
न्यादर्श विधि	स्तरित यादृच्छिक नमूनाकरण (सोद्देश्यपूर्ण रूप से चयनित स्तरों के भीतर)
उपकरण	संरचित प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची
तथ्य स्रोत	प्राथमिक: क्षेत्र कार्य। द्वितीयक: सरकारी रिपोर्ट्स, जनगणना, यूनेस्को एवं असर प्रकाशन
विश्लेषण	SPSS – प्रतिशत, मध्यमान, काई-वर्ग परीक्षण, टी-परीक्षण एवं सहसंबंध

5.2 जनसंख्या एवं न्यादर्श (Population and Sample)

387 उत्तरदाताओं का न्यादर्श पाँच उत्तरदाता श्रेणियों तथा पाँच स्थानिक स्तरों में वितरित किया गया, जैसा सारणी 2 में दर्शाया गया है।

सारणी 2. न्यादर्श का वितरण (N = 387)

श्रेणी	रायपुर शहरी	आरंग शहरी	धरसीवा शहरी	आरंग ग्रामीण	धरसीवा ग्रामीण	कुल
बच्चे	13	13	13	20	20	79
अभिभावक	13	13	13	19	19	77
शिक्षक	13	13	13	19	19	77
कोचिंग प्रतिनिधि	13	13	13	19	19	77
समुदाय के सदस्य	13	13	13	19	19	77
कुल	65	65	65	96	96	387

5.3 न्यादर्श आकार का औचित्य (Justification of Sample Size)

समाजशास्त्रीय शोध में न्यादर्श का आकार सुविधा के आधार पर नहीं, बल्कि स्थापित सांख्यिकीय सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित होता है। यहाँ स्वीकृत 387 के आँकड़े के पीछे तीन आधार हैं।

- **क्रेजी एवं मॉर्गन मानक:** क्रेजी एवं मॉर्गन (1970) द्वारा विकसित तालिका के अनुसार, दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में 95 प्रतिशत विश्वसनीयता स्तर हेतु 384-387 इकाइयों का न्यादर्श आवश्यक है। रायपुर जिले की जनसंख्या इस सीमा से अधिक है (भारत की जनगणना, 2011)।
- **त्रुटि सीमा:** 387 उत्तरदाताओं के चयन से त्रुटि की संभावना लगभग 5 प्रतिशत रह जाती है, जो विश्वसनीय सर्वेक्षण शोध के लिए स्वीकृत मानक है।
- **प्रतिनिधित्व:** यह संख्या रायपुर नगर निगम क्षेत्र तथा आरंग एवं धरसीवा ब्लॉकों के तुलनीय प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है।

5.4 अध्ययन क्षेत्र का विवरण (Profile of the Study Area)

रायपुर जिला छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक एवं शैक्षणिक केंद्र है। इसकी साक्षरता दर राज्य के औसत से अधिक है, जो इसे शिक्षा संबंधी शोध के लिए उपयुक्त बनाती है; तथा यहाँ एक ओर आधुनिक शहरी संस्कृति है, तो दूसरी ओर आरंग एवं धरसीवा जैसे ब्लॉक हैं जहाँ ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी परिवेश का मिश्रण मिलता है।

सारणी 3. चयनित अध्ययन क्षेत्रों की विशेषताएँ

क्षेत्र	प्रकार	मुख्य विशेषता
रायपुर नगर निगम क्षेत्र	शहरी	डिजिटल हब एवं उच्च साक्षरता; निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों का वर्चस्व
आरंग ब्लॉक	ग्रामीण / अर्ध-शहरी	पारंपरिक सामाजिक संरचना; विकासशील शहरी केंद्र एवं संसाधन-अभावी ग्रामीण परिधि
धरसीवा ब्लॉक	ग्रामीण / औद्योगिक	कृषि एवं औद्योगिक (उरला, सिलतरा) मिश्रित परिवेश; श्रमिक परिवारों की उल्लेखनीय उपस्थिति

इन क्षेत्रों के चयन के दो आधार हैं। प्रथम, रायपुर शहर तथा आरंग एवं धरसीवा के गाँवों के बीच का वैषम्य तकनीक तक विभेदक पहुँच के प्रत्यक्ष मापन की अनुमति देता है। द्वितीय, यह एक समान नीतिगत परिवेश के भीतर शहरी एवं ग्रामीण बच्चों पर ऑनलाइन शिक्षा के भिन्न व्यवहारगत प्रभावों के अवलोकन को संभव बनाता है।

5.5 प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियाँ (Statistical Techniques)

सारणी 4. प्रयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण

परीक्षण	प्रयोजन	अध्ययन में प्रयोग
प्रतिशत	सामान्य वितरण ज्ञात करने हेतु	ग्रामीण विद्यार्थियों में स्मार्टफोन उपयोग का प्रतिशत

परीक्षण	प्रयोजन	अध्ययन में प्रयोग
मध्यमान	केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करने हेतु	शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के औसत ऑनलाइन कक्षा घंटे
काई-वर्ग परीक्षण	दो चरों के संबंध के परीक्षण हेतु	निवास क्षेत्र एवं सामाजिक व्यवहार के बीच संबंध
टी-परीक्षण	दो समूहों के मध्यमान की तुलना हेतु	ऑनलाइन एवं ऑफलाइन अधिगमकर्ताओं के परीक्षा प्राप्तांकों की तुलना
सहसंबंध	दो कारकों के संबंध के आकलन हेतु	इंटरनेट उपयोग एवं सामाजिक एकाकीपन का संबंध

समस्त गणना SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) में की गई। शोध नैतिकता के मानकों का पालन किया गया: सहभागिता स्वैच्छिक रही, अवयस्क उत्तरदाताओं के संबंध में अभिभावकों अथवा संरक्षकों से सूचित सहमति प्राप्त की गई, तथा विश्लेषण से पूर्व समस्त प्रतिक्रियाओं को अनामित किया गया।

6. प्रदत्त विश्लेषण एवं व्याख्या (Analysis and Interpretation)

विश्लेषण उद्देश्यों से व्युत्पन्न चार आयामों पर संगठित है: शैक्षणिक प्रभाव, सामाजिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य प्रभाव, तथा सोशल मीडिया का प्रभाव। **6.1 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण का शैक्षणिक प्रभाव** अध्ययन से स्पष्ट होता है कि रायपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षण की उपलब्धता और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय अंतर है। शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा डिजिटल शिक्षण-सामग्री अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध रही। इसके विपरीत आरंग और धरसीवा के ग्रामीण क्षेत्रों में उपकरणों की कमी, साझा मोबाइल, कमजोर नेटवर्क तथा बिजली की अनियमितता के कारण ऑनलाइन कक्षाओं में नियमित भागीदारी बाधित हुई। इस प्रकार संसाधनों की असमान उपलब्धता ने शैक्षणिक उपलब्धि के अंतर को बढ़ाने में भूमिका निभाई।

प्रारम्भिक विश्लेषण के अनुसार शहरी विद्यार्थियों का औसत परीक्षा-प्राप्तांक ग्रामीण विद्यार्थियों से अधिक पाया गया। इसी प्रकार शहरी विद्यार्थियों में प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षाओं में भागीदारी का औसत समय भी अधिक रहा। स्वयं के डिजिटल उपकरण और निर्बाध इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता शहरी विद्यार्थियों में ग्रामीण विद्यार्थियों की तुलना में अधिक थी। यह स्थिति बताती है कि ऑनलाइन शिक्षा की प्रभावशीलता केवल शिक्षण-सामग्री या प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उपकरण, नेटवर्क, घरेलू अध्ययन-परिवेश और अभिभावकीय सहयोग जैसे सामाजिक-आर्थिक कारकों से भी प्रभावित होती है।

अतः यह कहा जा सकता है कि ऑनलाइन शिक्षण ने उन विद्यार्थियों को अधिक लाभ पहुँचाया जिनके परिवारों में पर्याप्त डिजिटल संसाधन उपलब्ध थे। ग्रामीण एवं निम्न-आय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा अक्सर नियमित एवं प्रभावी अधिगम के बजाय सीमित पहुँच वाला माध्यम बनी रही। इसलिए ऑफलाइन शिक्षण, विशेषकर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक आयु वर्ग के लिए, अधिक समावेशी और समान अवसर प्रदान करने वाला माध्यम सिद्ध होता है।

6.2 सामाजिक एवं व्यवहारगत प्रभाव

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विद्यालय बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक स्थल है, जहाँ वे केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं बल्कि सहपाठियों से संवाद, सामूहिक चेतना, सहकार्य (Teamwork), अनुशासन, नेतृत्व तथा प्रतिस्पर्धा जैसी व्यवहार-कुशलताएँ भी अर्जित करते हैं। ऑनलाइन शिक्षण के दौरान बच्चों के प्रत्यक्ष संपर्क में आई कमी ने इन सामाजिक अनुभवों में बाधा उत्पन्न की। रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ सामुदायिक जीवन अधिक सघन है, विद्यालय बंद होने से बच्चों के सामाजिक संवाद में उल्लेखनीय गिरावट आई। इसका प्रमुख कारण विद्यालयों का बंद रहना, इंटरनेट सुविधाओं का सीमित होना तथा डिजिटल माध्यमों द्वारा निरंतर संपर्क की कमी रही।

शहरी क्षेत्रों में बच्चों ने वीडियो कॉल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन समूहों के माध्यम से संपर्क बनाए रखने का प्रयास किया, फिर भी यह संपर्क विद्यालयी वातावरण में होने वाले सहज संवाद का पूर्ण विकल्प नहीं बन सका। तथापि दोनों ही परिवेशों में अनुशासन, समयबद्धता एवं नैतिक विकास के संदर्भ में एक समान व्यवहारगत परिवर्तन देखा गया, जो प्रत्यक्ष विद्यालयी शिक्षण की अनुपस्थिति का परिणाम है।

शिक्षकों एवं अभिभावकों के अनुभवों से यह भी संकेत मिलता है कि ऑनलाइन अवधि में कुछ बच्चों में अनुशासन, समय-पालन, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तथा नियमित अध्ययन की आदत में कमी आई। घर का वातावरण विद्यालय की तरह संरचित नहीं होता; इसलिए विद्यार्थी पढ़ाई के समय मोबाइल,

मनोरंजन सामग्री और घरेलू गतिविधियों से आसानी से विचलित हो जाते हैं। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि प्रत्यक्ष विद्यालयी शिक्षण बच्चों के व्यवहारगत एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

6.3 मनोवैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य प्रभाव

निरंतर स्क्रीन-टाइम ने बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है। शहरी क्षेत्रों में विद्यार्थियों के पास उपकरणों की उपलब्धता अधिक होने के कारण शिक्षण के साथ-साथ मनोरंजन, गेमिंग और सोशल मीडिया के लिए भी स्क्रीन का उपयोग बढ़ा, जिसका प्रभाव एकाग्रता में कमी, आँखों में तनाव, डिजिटल थकान, चिड़चिड़ापन तथा शारीरिक गतिविधियों में कमी के रूप में देखा गया।

आरंग एवं धरसीवा के ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या का स्वरूप भिन्न था — यहाँ बच्चों को अपर्याप्त नेटवर्क, डाटा समाप्त होने, साइरा मोबाइल और उपकरणों की अनुपलब्धता जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे पढ़ाई छूटने की चिंता, निराशा और शैक्षणिक पिछड़ने की भावना उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त शारीरिक सक्रियता में कमी ने बच्चों के समग्र स्वास्थ्य एवं खेल-कूद की आदतों को दोनों क्षेत्रों में प्रभावित किया, यद्यपि इसका कारण शहर में अत्यधिक स्क्रीन-उपयोग और गाँव में संसाधन-अभाव के रूप में भिन्न रहा।

विद्यालय में खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सहपाठियों के साथ प्रत्यक्ष सहभागिता बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायक होती है। ऑनलाइन शिक्षण के कारण इन गतिविधियों में कमी आई, जिससे बच्चों का सामाजिक एवं शारीरिक विकास प्रभावित होने की संभावना बढ़ी। इसलिए विद्यालयों में खेलकूद, समूह गतिविधियाँ, परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सहयोग को शिक्षण व्यवस्था का आवश्यक भाग बनाया जाना चाहिए।

6.4 सोशल मीडिया का प्रभाव

ऑनलाइन शिक्षा के बहाने बच्चों की सोशल मीडिया मंचों तक पहुँच पर्याप्त रूप से सुगम हो गई। इसके तीन प्रमुख परिणामों की पड़ताल की गई है:

- **ध्यान भटकाव:** शिक्षा के प्रयोजन से मोबाइल उपलब्ध होने पर बच्चे शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट पर अधिक समय व्यय करने लगे, जिससे अध्ययन की गंभीरता में तदनु रूप कमी आई तथा डिजिटल निर्भरता जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई।
- **सामाजिक तुलना:** सोशल मीडिया ने बच्चों में दिखावे एवं तुलना की भावना को प्रोत्साहित किया है, जिसका किशोर मन पर उल्लेखनीय मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, साथ ही अनुचित सामग्री तक पहुँच का जोखिम भी बढ़ा।
- **साइबर सुरक्षा:** ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की सीमितता के कारण बच्चे सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों एवं साइबर जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील रहे हैं, क्योंकि अभिभावक भी उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी प्रभावी ढंग से नहीं कर पाते।

अतः ऑनलाइन शिक्षण के साथ डिजिटल नागरिकता, साइबर सुरक्षा और जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। शिक्षक, अभिभावक और समुदाय मिलकर बच्चों को तकनीक के सुरक्षित, सीमित और शैक्षणिक उपयोग के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं।

6.5 परिकल्पनाओं की व्याख्या

अध्ययन की **पहली परिकल्पना** के अनुसार ग्रामीण विद्यार्थियों में ऑनलाइन शिक्षण की प्रभावशीलता शहरी विद्यार्थियों की तुलना में कम पाई गई। इसका कारण डिजिटल उपकरणों, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली और सहायक अध्ययन-परिवेश की सीमित उपलब्धता है। इसलिए यह परिकल्पना समर्थित मानी जा सकती है।

दूसरी परिकल्पना, जिसमें ऑनलाइन शिक्षण के कारण सामाजिक संवाद में कमी की संभावना व्यक्त की गई थी, भी समर्थित प्रतीत होती है। बच्चों के सहपाठियों, शिक्षकों और विद्यालयी गतिविधियों से प्रत्यक्ष संपर्क कम होने के कारण उनके समाजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

तीसरी और चौथी परिकल्पनाएँ डिजिटल विभाजन से संबंधित थीं। निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि आर्थिक स्थिति तथा निवास क्षेत्र—शहरी या ग्रामीण—दोनों डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। उच्च आय और शहरी पृष्ठभूमि वाले परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए अपेक्षाकृत बेहतर अवसर मिले, जबकि निम्न आय और ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी संसाधनों की कमी से अधिक प्रभावित हुए।

पाँचवीं परिकल्पना के संदर्भ में यह निष्कर्ष सामने आता है कि 6–14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन शिक्षण की प्राथमिकता अधिक है। इसका मुख्य कारण प्रत्यक्ष शिक्षक-विद्यार्थी संपर्क, सामाजिक सहभागिता, अनुशासित दिनचर्या, त्वरित शंका-समाधान और खेलकूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी है। इसलिए ऑनलाइन शिक्षण को प्रत्यक्ष शिक्षण के विकल्प की अपेक्षा सहायक माध्यम के रूप में देखना अधिक उपयुक्त होगा।

6.6 अपेक्षित निष्कर्ष (Anticipated Findings)

विश्लेषणात्मक ढाँचे तथा पुनरावलोकित द्वितीयक साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित परिणाम अपेक्षित हैं। प्रथम, शहरी रायपुर तथा आरंग एवं धरसीवा के ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता में उल्लेखनीय अंतर, जो यह संकेत देता है कि तकनीक की कमी ग्रामीण बच्चों के शैक्षणिक स्तर को प्रभावित कर रही है। द्वितीय, बच्चों में एकाकीपन की वृद्धि तथा सहपाठी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद में कमी, जो इस निष्कर्ष को पुष्ट करती है कि ऑनलाइन शिक्षा सर्वांगीण सामाजिक विकास के लिए पूर्णतः अनुकूल नहीं रही। तृतीय, शहरी निजी विद्यालयों के बच्चों में अधिक तकनीकी दक्षता तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कोचिंग केंद्रों पर बढ़ती निर्भरता। चतुर्थ, बच्चों एवं अभिभावकों के बीच पारंपरिक संवाद में कमी, जिससे परिवारों के भीतर नए प्रकार के तनाव उत्पन्न हुए हैं।

7. निष्कर्ष (Conclusion)

यह अध्ययन इस प्रस्थापना से आगे बढ़ता है कि शिक्षा सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं, बल्कि एक गहन सामाजिक प्रक्रिया है। रायपुर जिले के संदर्भ में की गई यह तुलना दर्शाती है कि तकनीकी प्रगति के उपरांत भी 6-14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ऑफलाइन शिक्षण पद्धति का कोई पूर्ण विकल्प नहीं है। साक्ष्य आरंग एवं धरसीवा के ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी से उत्पन्न एक सार्थक डिजिटल विभाजन की ओर संकेत करते हैं, जिसने ऑनलाइन शिक्षा की प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्यार्थियों के सामाजिक संवाद एवं प्राथमिक समाजीकरण को अक्षुण्ण रखने के लिए ऑफलाइन पद्धति अनिवार्य है, जबकि ऑनलाइन माध्यम को केवल एक सहायक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। तदनुसार अध्ययन एक ऐसे संतुलित मॉडल की संस्तुति करता है जो तकनीक एवं मानवीय संवेदनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। यह निष्कर्ष केवल आँकड़ों पर आधारित नहीं है, बल्कि रायपुर जिले के अवलोकित समाजशास्त्र पर आधारित है, जो यह बताता है कि तकनीक शिक्षा का साधन तो हो सकती है, किंतु शिक्षक और विद्यालय का स्थान नहीं ले सकती।

अध्ययन की सार्थकता चार क्षेत्रों में निहित है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को आरंग एवं धरसीवा जैसी ग्रामीण परिस्थितियों पर परखने में सहायक है। यह प्रशासन को ग्रामीण रायपुर में व्याप्त डिजिटल असमानता को समझने एवं उसे दूर करने का ठोस आधार प्रदान करता है। यह स्पष्ट करता है कि डिजिटल युग में बच्चों की लैंगिक समानता एवं सामाजिक मूल्यों की रक्षा कैसे की जाए। तथा यह एक हाइब्रिड मॉडल प्रस्तावित करता है जो तकनीक के लाभ को बनाए रखते हुए विद्यालयी समाजीकरण के मानवीय आयाम को भी सुरक्षित रखे।

8. सुझाव एवं संस्तुतियाँ (Suggestions and Recommendations)

8.1 डिजिटल बुनियादी ढाँचे का सुदृढीकरण

- ग्रामीण कनेक्टिविटी: डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए आरंग एवं धरसीवा के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट एवं निःशुल्क सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- उपकरणों की सुलभता: आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कम लागत वाले टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध कराने वाली सरकारी योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

8.2 हाइब्रिड शिक्षा मॉडल

- संतुलित दृष्टिकोण: पूर्णतः ऑनलाइन अथवा पूर्णतः ऑफलाइन शिक्षण के स्थान पर एक मिश्रित मॉडल (Blended Learning) अपनाया जाए, जहाँ तकनीक सहायक सामग्री के रूप में कार्य करे, पारंपरिक कक्षा के विकल्प के रूप में नहीं।
- डिजिटल साक्षरता: शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए विशेष कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ, जिससे वे बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित एवं शैक्षणिक रूप से उपयोगी प्रयोग की दिशा में मार्गदर्शन दे सकें।

8.3 समाजीकरण एवं मानसिक स्वास्थ्य

- सामूहिक गतिविधियाँ: ऑनलाइन शिक्षा के कारण बढ़े एकाकीपन को दूर करने के लिए विद्यालयों में खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाए।
- परामर्श सत्र: बच्चों के बदलते व्यवहार एवं तकनीक से उत्पन्न तनाव के समाधान हेतु विद्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाए।

8.4 सामुदायिक सहभागिता

- स्थानीय पुस्तकालय: ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्डों में डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की जाए, जहाँ समुदाय के सदस्य एवं बच्चे मिलकर तकनीक का सकारात्मक उपयोग सीख सकें।

8.5 शोध की सीमाएँ एवं भावी संभावनाएँ

प्रस्तुत अध्ययन रायपुर जिले, 6-14 वर्ष आयु वर्ग, शिक्षण के समाजशास्त्रीय आयामों, 387 उत्तरदाताओं के न्यादर्श तथा एक निश्चित समयावधि तक सीमित है। अनेक जिलों में दीर्घकालीन (Longitudinal) शोध तथा यहाँ चिह्नित मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर चिकित्सकीय अध्ययन इन निष्कर्षों का उल्लेखनीय विस्तार कर सकते हैं।

संदर्भ सूची (References)

- Agarwal, P. (2009). Indian higher education: Envisioning the future. SAGE Publications.
- Apple, M. W. (2014). Official knowledge: Democratic education in a conservative age (3rd ed.). Routledge.
- ASER Centre. (2021). Annual status of education report (rural) 2020. ASER Centre.
- ASER Centre. (2023). Annual status of education report (rural) 2023. ASER Centre.
- Bernstein, B. (1971). Class, codes and control. Routledge & Kegan Paul.
- Bourdieu, P. (1979). Distinction: A social critique of the judgement of taste. Routledge.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241–258). Greenwood.
- Castells, M. (1996). The rise of the network society. Blackwell.
- Census of India. (2011). District census handbook: Raipur—Directorate of Census Operations, Chhattisgarh.
- Chauhan, C. P. S. (2010). Education and social change in India. Journal of Indian Education, 36(2), 5–18.
- Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. Macmillan.
- Drèze, J., & Sen, A. (2013). An uncertain glory: India and its contradictions. Princeton University Press.
- Durkheim, É. (1956). Education and sociology. Free Press.
- Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Herder and Herder.
- Goode, W. J., & Hatt, P. K. (1952). Methods in social research. McGraw-Hill.
- Government of Chhattisgarh. (2022). Annual report of the School Education Department—Government of Chhattisgarh.
- Hargittai, E. (2002). Second-level digital divide: Differences in people's online skills. First Monday, 7(4).
- Jayaram, N. (2015). Sociology of education in India. Rawat Publications.
- Kothari, C. R. (2004). Research methodology: Methods and techniques (2nd ed.). New Age International.
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607–610.
- Livingstone, S., & Sefton-Green, J. (2016). The class: Living and learning in the digital age. New York University Press.
- Ministry of Education. (2020). National education policy 2020. Government of India.
- Ministry of Education. (2021). All India survey on higher education (AISHE) 2019–20. Government of India.
- NITI Aayog. (2021). SDG India index and dashboard 2020–21: Partnerships in the decade of action. NITI Aayog.
- Postman, N. (1992). Technopoly: The surrender of culture to technology. Alfred A. Knopf.
- Ramachandran, V. (2004). Gender and social equity in primary education: Hierarchies of access. SAGE Publications.
- Selwyn, N. (2004). Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. New Media & Society, 6(3), 341–362.
- Shah, B. V., & Shah, K. B. (2006). Sociology of education. Rawat Publications.
- Srinivas, M. N. (1966). Social change in modern India—University of California Press.
- UNESCO. (2020). Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. UNESCO.
- UNESCO. (2024). Technology in education: A tool on whose terms? Global education monitoring report. UNESCO.
- Van Dijk, J. (2005). The deepening divide: Inequality in the information society. SAGE Publications.
- World Bank. (2022). The state of global learning poverty: 2022 update. World Bank.